श्रीलंका में चीनी दखल से पैदा चुनौतियां

चीन अब हिंद-प्रशांत महासागरीय इलाके के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच पुनः राजनयिक रिश्ते कायम करवाकर चीन ने अरब खाड़ी इलाके में अमेरिकी प्रभाव को कमतर किया है। इसके अलावा रूस भी अपने विशाल ऊर्जा भंडारों के बूते भुजाएं फड़फड़ा रहा है और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में लगा है।

जी. पार्थसारथी

लेखक आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक हैं

पुनः राष्ट्र प्रमुख चुने जाने के बाद शी जिनपिंग और मुखर होकर एशिया में अमेरिकी ताकत के प्रभाव को चुनौती देंगे, ऐसे में भारत को चीन से लगती अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को सुदृढ़ करना जरूरी है। बेशक लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में हालिया चीनी घुसपैठों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है किंतु संपूर्ण थलीय और समुद्रीय सीमाओं पर भी यह लागू है। इसके अलावा, हिंद महासागरीय क्षेत्र में चीन की चालों पर विशेष तौर पर नज़र रखनी होगी। यह भी ज़हन में रखना जरूरी है कि बाइडेन प्रशासन ने तेल-संपन्न खाड़ी क्षेत्र को लेकर अमेरिकी विदेश नीति में ऊहापोह स्थिति बना डाली है। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक व्यवहार में अनाड़ीपन और असंवेदनशीलता दिखाते हुए इस अहम रिश्ते को बिगाड़ लिया है, जबकि ईरान के साथ संबंध पहले से ही तल्ख हैं। इसी बीच चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध पुनः अच्छे करने की मध्यस्थता निभाई है।

चीन अब हिंद-प्रशांत महासागरीय इलाके के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच पुनः राजनयिक रिश्ते कायम करवाकर चीन ने अरब खाड़ी इलाके में अमेरिकी प्रभाव को कमतर किया है। इसके अलावा रूस भी अपने विशाल ऊर्जा भंडारों के बूते भुजाएं फड़फड़ा रहा है और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में लगा है। अमेरिका को यह हकीकत माननी पड़ेगी कि रूस के बहिष्कार में भारत जैसे लोकतांत्रिक मित्र राष्ट्र साथ नहीं आने वाले, खासकर जब ऊर्जा हित दांव पर हों। हालांकि समूचे हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैन्य एवं आर्थिक ताकत का सामना करने में अमेरिका और भारत के हित एक समान हैं। इस जटिल परिस्थिति में, भारत ने अपने दो महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ व्यवहार में काफी दक्षता दिखाई है। चूंकि इन दोनों के चीन के साथ निकट संबंध हैं, जाहिर है इससे भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

चीन-पाकिस्तान रिश्ता मुख्यतः भारत-विरोधी नीति पर टिका है। यह ऐसा संबंध है जिसमें चीन से पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे हैं- परंपरागत और परमाणु। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम और नई दिल्ली से लेकर अंडमान-निकोबार द्वीप तक के इलाके को निशाना बनाने मे सक्षम पाकिस्तानी बैलेस्टिक मिसाइलें वस्तुतः चीनी डिज़ाइन की हैं। हालांकि हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 1980 के दशक में चले सिंहाला-तमिल जातीय संघर्ष के वक्त श्रीलंका में भारत के प्रति संशयों में उभार आया था। यह वह काल था जब एलटीटीई के साथ भारत के संबंध होने की खासी आशंका जताई गई थी। भारतीय कई बार भूल जाते हैं कि जातीय संघर्ष उत्तरी श्रीलंका तक ही सीमित रहा था, जहां तमिल सदियों से बसे हुए हैं। देश के दक्षिणी भाग में खेती करने वाले तमिल इसमें शामिल नहीं हुए थे। दक्षिणी तमिल, जिनके साथ हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातें हुई हैं, वे उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं।

फिलहाल श्रीलंका विकट आर्थिक संकट से गुजर रहा है, पाकिस्तान भी ठीक इसी स्थिति में है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका को गंभीर विदेशी मुद्रा संकट से उबारने को 4 बिलियन डॉलर की राहत राशि देने घोषणा की तो एक तरह से कंगाल हुई पड़ी श्रीलंकाई सरकार को आश्चर्यजनक खुशी हुई और काफी अभिभूत भी हुई। रोचक यह कि इसके बाद, देर से जगी चीन सरकार ने भी आनन-फानन में राहत राशि देने की बात कही, किंतु महज 1 बिलियन डॉलर। अनेक पर्यवेक्षकों को यकीन है कि श्रीलंका का मौजूदा आर्थिक संकट अनाप-शनाप खर्चों और बिना सोचे-समझे बहुत ऊंची ब्याज दर पर इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स (आईएसबी) आधारित ऋण लेने से बना है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाईना ने श्रीलंका को ऋण वापसी में दो साल की छूट देने की पेशकश की है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने में भी सहायता करेगा। लेकिन असल में, चीन ने श्रीलंका के सिर चढ़ा ऋण बोझ कम करने में बहुत कम यत्न किया है।

दरअसल, चीन ने अन्य मुल्कों की भांति श्रीलंका को भी कर्ज-मकड़जाल में फंसा रखा है। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि श्रीलंका ने चीनी सहयोग से अनेक परियोजनाएं बनाने हेतु ऋण लिया, इसमें दक्षिणी तट पर स्थित हम्बनतोता बंदरगाह का विकास कार्य मुख्य था। बंदरगाह से पैदा होने वाली कुल कमाई को नज़रअंदाज करते हुए यह कर्ज लिया गया। हम्बनतोता बंदरगाह पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे के चुनाव क्षेत्र में आता है। इस बंदरगाह का प्रशासन और कामकाज अब एक तरह से चीन के हाथ में है और यह हिंद महासागर में गश्त करते चीनी नौसैन्य जहाज और पनडुब्बियों का पड़ाव बन चुका है। कहीं कोलोम्बो बंदरगाह की हालत भी ऐसी न हो जाए, भारत ने चीन की उपस्थिति को लेकर कड़ा एतराज जताया था। भारत पहुंचने वाली वस्तुओं का विशाल भाग, जिसमें संवेदनशील उपकरण भी शामिल हैं, इस बंदरगाह से होकर आता है। इस बीच, सूचना है अडाणी ग्रुप ने लगभग 700 मिलियन डॉलर का निवेश कर वेस्ट कॉन्टेनर टर्मिनल नामक एक अलग आवाजाही बंदरगाह सुविधा हासिल कर ली है।

पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और पूरे राजपक्षे परिवार के खिलाफ बने जनाक्रोश उपरांत श्रीलंका संसद के अनुमोदन से वरिष्ठ नेता रनिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। विक्रमसिंघे ने लगभग ध्वस्त पड़ी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सावधानी भरे और प्रभावशाली कदम उठाए हैं। इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की दरियादिल मदद के लिए तमाम श्रीलंकाई शुक्रगुजार हैं। जिस तरह विदेश मंत्री जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आपातकाल में सहायतार्थ त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई है, उसकी भी भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है।

अपनी एकदम हालिया कोलम्बो यात्रा के दौरान अपने श्रीलंकाई मित्रों से हुई मुलाकातों में बातचीत में पाया कि पिछले दिनों में भारत ने बहुत साख अर्जित की है। अब इसके साथ अन्य विषयों पर भी आगे बढ़ना होगा। बतौर आस्थावान बौद्ध, सिंहाला लोग बोध-गया की यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाओं की आस रखते हैं। लिहाजा बोध-गया तक रेल सेवा में सुधार लाने के अलावा भारत में रिहायश के दौरान सुविधाओं में सुधार करने के लिए संयुक्त निगरानी उपाय करने चाहिए। आपसी व्यापार, पर्यटन और निवेश में भुगतान रुपि-ऐप से करने को बढ़ावा देने हेतु अनेकानेक उपाय करने की जरूरत है। तलाईमन्नार-रामेश्वरम नौका-फेरी को पुनः शुरू करके आवाजाही आसान की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि आने वाले महीनों में त्रिकोणमली बंदरगाह से काम शुरू होने जा रहा है, सो नये द्विपक्षीय आर्थिक अवसर पैदा होना निश्चित है।

श्रीलंका में भारतीयों के निजी निवेश को बढ़ावा और उत्साहित करने को भारत और श्रीलंका को मिलकर कल्पनाशीलता से काम करना चाहिए। जब भारत और श्रीलंका निवेश, व्यापार में रुपि-ऐप से भुगतान को बढ़ावा देने में लगे हैं, ऐसे में वहां निजी निवेशकों के लिए बहुत बड़ी संख्या में मौके हैं, मसलन, हवाई अड्डे, होटल उद्योग और उच्च शिक्षा। श्रीलंका में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले वहां की अपनी कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों वाली पारी सफलतापूर्वक पूरी करने जा रहे हैं।